अमर उजाला

नई दिल्ली | बुधवार, 10 अप्रैल 2019

# प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

अपने जीवन का पूरा आनंद लें और हमेशा सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें...
- मैट कैमरून

अमेरिकी संगीतकार

**एक विधानसभा क्षेत्र में पांच ईवीएम से वीवीपैट पर्ची के मिलान करने के सर्वोच्च अदालत के आदेश से ईवीएम को लेकर संदेह दूर हो जाना चाहिए। ईवीएम को राजनीतिक मुद्दा बनाने से निर्वाचन आयोग जैसी संस्था की प्रतिष्ठा पर ही आंच आती है।**

## संदेह और समाधान

**सर्वोच्च** अदालत ने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हर विधानसभा क्षेत्र में पांच ईवीएम से वीपीपैट पर्चियों (वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) का मिलान करने का आदेश दिया है, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और मजबूत होगी। यह अहम है कि सर्वोच्च अदालत का यह आदेश 11 अप्रैल से शुरू हो रहे लोकसभा के पहले चरण के चुनाव से लागू हो जाएगा। हालांकि 21 विपक्षी दलों ने अपनी याचिका में पचास फीसदी ईवीएम से वीवीपैट मिलान करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया है। चुनाव आयोग ने अपनी दलील में कहा था कि इतनी अधिक संख्या में वीवीपैट के मिलान करने से मतगणना में छह दिन लग सकते हैं और इसके लिए अतिरिक्त तैयारी भी करनी पड़ेगी। जबकि निर्वाचन नियम के तहत एक विधानसभा क्षेत्र में औचक रूप से एक ईवीएम से वीवीपैट पर्ची का मिलान करने का प्रावधान है। किसी भी लोकतांत्रिक देश की मजबूती के लिए जरूरी है कि उसकी निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो और इस मामले में भारत दुनिया में एक मिसाल है। कहने की जरूरत नहीं है कि देश की निर्वाचन प्रक्रिया में ईवीएम के आगमन के बाद से चुनावी धांधिलयों पर अंकुश लगा है। इसके बावजूद तमाम राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और उनके संदेह के कारण सर्वोच्च अदालत ने ही 2013 में चुनाव आयोग को ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ने के निर्देश दिए थे। निर्वाचन आयोग का दावा है कि भारत में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम किसी बाहरी नेटवर्क से नहीं जुड़ी होती और इसे हैक नहीं किया जा सकता। विपक्षी दलों की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की निष्पक्षता को परखने के लिए राजनीतिक दलों को इसे हैक करने की चुनौती तक दी थी, जिसमें विपक्षी दलों ने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मार्च, 2017 के बाद हुए तमाम चुनावों में 1,500 मतदान केंद्रों में वीपीपैट पर्चियों का ईवीएम से मिलान किया गया था और ये सही पाई गई थीं। सर्वोच्च अदालत के ताजा फैसले से मतगणना में पांच घंटे तक की देरी होगी, जिससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा; इससे ईवीएम को लेकर उठ रहा संदेह जरूर दूर हो जाना चाहिए। ईवीएम को राजनीतिक मुद्दा बनाने से निर्वाचन आयोग जैसी संस्था की प्रतिष्ठा पर ही आंच आती है।

# अतीत से निकलता मालदीव

**मालदीव पारंपरिक रूप से नई दिल्ली के प्रभाव में रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक, सोलिह की मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की संसदीय चुनाव में जीत भारत के हित में एक अच्छी खबर है।**

**माइक इव्स**

मालदीव के राष्ट्रपति की अगुआई वाले राजनीतिक दल ने सप्ताहांत में हुए संसदीय चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की है। इस जीत से उन्हें रणनीतिक रूप से अहम इस देश में राजनीतिक स्वतंत्रता को बहाल करन में मदद मिल सकती है, जिसका अतीत तानाशाही से जुड़ा रहा है।

राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने सितंबर में राष्ट्रपति चुनावों में शानदार जीत हासिल की थी। लेकिन उनकी पार्टी का कुछ एजेंडा स्थगित हो गया, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल उनके कुछ सहयोगी ने पूर्व कद्दावर नेता अब्दुल्ला यामीन के साथ गठजोड़ कर लिया, जिन पर व्यापक रूप से भ्रष्टाचार और दमन का आरोप लगाया गया है।

भारत के दक्षिण-पश्चिम में द्वीपों की शृंखला का देश मालदीव पारंपरिक रूप से नई दिल्ली के प्रभाव में रहा है। फिर यह समुद्री मार्गों तक फैला है, जो चीन के लिए भी महत्वपूर्ण है और बीजिंग ने हाल ही में मालदीव में आधारभूत परियोजनाओं पर करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं। आलोचकों ने मालदीव को चीन के 'कर्ज में फंसाने की कूटनीति' के बारे में चेताया था। इसका मतलब यह है कि चीन बड़े ऋण चुकाने के रूप में सुरक्षा रियायतों की पेशकश करने का दबाव डाल सकता है। पश्चिम समेत भारत के कुछ कूटनीतिज्ञों ने मालदीव को चेताया था कि चीन पर बढ़ती निर्भरता मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरनाक हो सकती है।

कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने पिछले साल सोलिह (जिन्हें चीन के प्रभाव पर संदेह रहा है) की जीत को भारत के हित में एक अच्छी खबर के रूप में देखा था। बीते रविवार को भारत के एक अंग्रेजी दैनिक में एक खबर छपी, जिसमें सोलिह की मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की संसदीय चुनाव में जीत को नई दिल्ली के लिए 'पड़ोस' में एक 'सकारात्मक घटनाक्रम' बताया गया। फिर भी नई दिल्ली स्थित ब्रूकिंग्स इंडिया में विदेश नीति फेलो कोन्स्टान्टिनो जेवियर कहते हैं कि 'सस्ते और आसान पैसे के लालच ने इस आशंका को बढ़ा दिया है कि मालदीव के नेताओं द्वारा चीन के खिलाफ सार्वजनिक बयानों के बावजूद चीन के साथ मालदीव का रिश्ता और गहरा होगा।' उनका कहना है कि 'दीर्घकाल में मालदीव के किसी भी नेता की स्वाभाविक प्रवृत्ति चीन के साथ संबंधों को बढ़ाने की होगी। चीन के पास वह वित्तीय शक्ति है, जिससे वह तेजी से और प्रभावी ढंग से उसकी जरूरतों की पूर्ति कर सकता है।'

मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने देश की संसद की 87 सीटों में से दो तिहाई से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। मालदीव के 2008 में हुए पहले स्वतंत्र चुनाव के बाद से संसद में बहुमत हासिल करने वाली पहली पार्टी बनने के लिए उसे सिर्फ 44 सीटों की जरूरत थी। स्थानीय समाचार वेबसाइट *द मालदीव इंडिपेंडेंट* के अनुसार, अन्य पार्टियों में से प्रत्येक ने सात से कम सीटें जीतीं।

मालदीव में पिछले चुनावों के दौरान व्यापक अनियमितताओं का आरोप लगा था। यामीन पर पिछले साल राष्ट्रपति के चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के कर्मचारियों को उनकी पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर किया, निर्वाचन आयोग में अपने वफादारों की नियुक्ति की, विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया और मतदाता पंजीकरण को रद्द कर दिया।

लेकिन मालदीव के चुनाव पर निगरानी रखने वाली संस्था ट्रांसपैरेंसी मालदीव ने रविवार को एक बयान में कहा कि पिछला मतदान पारदर्शी और अच्छे ढंग से कराया गया था। सप्ताहांत पर सोलिह ने एक बयान में कहा कि देश के लोग चुनाव में 'सबसे बड़े विजेता' थे। उन्होंने कहा कि 'हमारा प्रचार अभियान मुद्दों पर आधारित था, नफरत और संकीर्ण विभाजन पर नहीं, यह हमारे युवा लोकतंत्र की जीत है। हमारी सरकार ने उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने में कोई बाधा नहीं डाली, जिनसे हम असहमत थे। यह हमारे लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है।'

पिछली सर्दियों में मालदीव अंतरराष्ट्रीय मीडिया में तब सुर्खियों में था, जब तत्कालीन राष्ट्रपति यामीन ने आपातकाल की घोषणा करके और सर्वोच्च न्यायालय को घेरने के लिए सेना भेजकर एक राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया था। ऐसा कदम उन्होंने अपने नौ विरोधियों के खिलाफ आपराधिक आरोपों को निरस्त करने के बाद उठाया था।

उनमें से एक मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद थे, जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं और उस समय लंदन में निर्वासन में रह रहे थे। वर्ष 2018 के अंत में मालदीव लौटने वाले नाशीद सितंबर में हुए चुनाव में भाग लेने के लिए अयोग्य थे, क्योंकि यामीन सरकार ने उन्हें जेल की सजा सुनाई थी। तब नाशीद की जगह पर सोलिह ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था।

पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान सोलिह ने वादा किया था कि अगर वह चुनाव जीत जाएंगे, तो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को बहाल करेंगे, जिसमें मानहानि विरोधी कानून को हटाने की बात भी शामिल थी, जिसे यामीन ने अपने विरोधियों को जेल में बंद करने के हथियार के रूप में लाया था। जीतने के दो महीने बाद सोलिह ने मानहानि विरोधी कानून को निरस्त कर दिया, लेकिन सोलिह की पार्टी को हाल के महीनों में अपने एजेंडे को लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए, सोलिह ने एक प्रमुख पत्रकार और यामीन के आलोचक अहमद रिलवान अब्दुल्ला की 2014 में हुई गुमशुदगी की जांच का वादा किया था, लेकिन मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल एक पार्टी ने फरवरी में चोरी हुई संपत्ति और अनसुलझी हत्याकांडों की जांच से संबंधित विधेयक पर मतदान करने से इनकार कर दिया।

पूर्व कद्दावर राष्ट्रपति यामीन को हाल ही में देश के पर्यटन बोर्ड में हुए एक भ्रष्टाचार कांड में जेल में डाला गया। उन्होंने आरोपों से इनकार किया और संसदीय चुनाव से कुछ दिन पूर्व ही मार्च में उन्हें जमानत मिली है।

© The New York Times 2019

**अंतर्ध्वनि**

>> बालकृष्ण भट्ट

## शब्द की शक्ति सभी जीवों को मुग्ध कर देती है

*शब्द की आकर्षण शक्ति न्यूटन की आकर्षण शक्ति से जरा भी कम नहीं कही जा सकती। बल्कि शब्द की इस शक्ति को न्यूटन की आकर्षण शक्ति से विशेष कहना चाहिए। इसलिए कि जिस आकर्षण शक्ति को न्यूटन ने प्रकट किया है, वह केवल प्रत्यक्ष में काम दे सकती है। सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, पृथ्वी चंद्रमंडल को, यों ही जितने बड़े पदार्थ हैं सब छोटे को आकर्षित कर रहे हैं। किंतु एक पदार्थ दूसरे को तभी आकर्षित करते हैं, जब वे दोनों एक दूसरे मुकाबले में हों।*

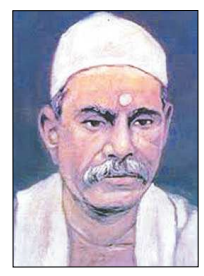

*पर शब्द की आकर्षण शक्ति में यह आवश्यक नहीं है कि शब्द की आकर्षण शक्ति तभी ठहर सकती है, जब नेत्र भी वहां योग देता हो। इन शब्दों का जितना ही अधिक समूह बढ़ता जाएगा, उतनी ही उनमें आकर्षण शक्ति भी अधिक होती जाएगी। प्रत्येक जाति के धर्म ग्रंथ इसके प्रमाण हैं। वेदादि धर्म-ग्रंथ जो इतने माननीय हैं, सो इसीलिए कि उनमें धर्म का उपदेश ऐसे शब्द समूहों में है, जो चित्त को अपनी ओर खींच लेते हैं और चित्त में गड़ के ऐसे बैठ जाते हैं कि हटाए नहीं हटते। वृक्ष से फल का टूट कर नीचे गिरना साधारण-सी बात है, पर किसी के मन में इसका कोई असर नहीं होता। शब्द की आकर्षण शक्ति में इतना असर है कि वह मनुष्य की कौन कहे, वन के मृगों एवं अन्य प्राणियों को भी मुग्ध कर देती है। कोयल का पंचम स्वर में अलापना सबको क्यों भाता है, इसीलिए कि मीठी आवाज सबको सुखद है। बीन इत्यादि भी लोगों को क्यों रुचते हैं, इसीलिए कि वे कान को सुखद और मन को आकर्षित करने वाले हैं। केवल शब्द की मधुर ध्वनि में जब इतना प्रलोभन है, तब यदि उन शब्दों में अर्थचातुरी भी भरी हो, तो वह कितना मन को खींचने वाला होगा।*

*-दिवंगत हिंदी साहित्यकार*

**मंजिलें और भी हैं**

>> दीपा परब

## लड़कियां भी बन सकती हैं बाउंसर

**मैं** महाराष्ट्र पुलिस की नौकरी करना चाहती थी। इसके लिए मुंबई में मैं ट्रेनिंग ले रही थी। अपने खर्च पूरे करने के लिए मैं दिन में मेक अप या जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम कर रही थी। वहां काम करते हुए मैंने पहली बार बॉडीगार्ड्स को नजदीक से काम करते देखा। कद्दावर कदकाठी के ये शख्स सेट्स पर अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को घेरे रहते थे। ये लोग काले रंग की यूनिफॉर्म पहने होते थे। मेरे मन में उनके काम को जानने की उत्सुकता पैदा हुई। मैंने अवसर देखकर उनसे बात करना शुरू कर दिया और जानना चाहा कि आखिर वे काम क्या करते हैं और क्या मैं भी बाउंसर की तरह काम कर सकती हूं। जब उन्हें पता चला कि मैंने पुलिस की ट्रेनिंग ले रखी है, तो उन्होंने कहा कि मैं बाउंसर की तरह काम कर सकती हूं। इसके बाद कुछ कार्यक्रमों में मैं भी उनके साथ जाने लगी। बाउंसर के तौर पर मैं काम जरूर करने लगी थी, लेकिन मुझे और मेरी तरह अन्य महिला बाउंसरों को पबों और कंसर्ट में महिलाओं के वॉशरूम के बाहर खड़ा कर दिया जाता था। मैंने जब बड़ी जिम्मेदारी मांगी, तो मुझसे कहा गया कि महिला होने के नाते मैं भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सकती, इसलिए मुझे बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल सकती। फिर मुझे अपनी सीमाओं का एहसास हुआ, लेकिन मैंने पुणे अपने घर लौटने और वहां अपनी अकादमी बनाने का फैसला कर लिया। इस तरह मेरी 'रणरागिनी' अकादमी अस्तित्व में आई। मुझे ऐसी महिलाओं की तलाश थी, जो अच्छी कद काठी की हों। आखिर बाउंसर को भीड़ में अलग से पहचान में आना चाहिए। हमने 12 महिलाओं के साथ शुरुआत की। हमें पहला काम गणेशोत्सव के समय मिला। हमें महिलाओं और बुजुर्गों की देखभाल करने की जिम्मेदारी मिली। मैं यह कह सकती हूं कि हमने अच्छे से यह काम किया, जिसकी वजह से हमें न केवल ऐसी महिलाओं के फोन आए, जो बाउंसर बनना चाहती थीं, बल्कि इवेंट मैनेजर्स ने भी हमसे अपने आयोजनों के लिए संपर्क किया। जून, 2016 में की गई हमारी छोटी सी शुरुआत देखते ही देखते रंग लाने लगी। महज तीन वर्ष के भीतर हमारी अकादमी से 540 महिला बाउंसर जुड़ चुकी हैं। हमारा यह काम महिलाओं में नया आत्म विश्वास तो पैदा कर ही रहा है, उन्हें आर्थिक रूप से आत्म निर्भर भी बना रहा है। मसलन, हमारे साथ काम करने वाली अदिति (नाम बदला हुआ) को ही देखिए। उसका पति हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता था। वह अपने परिवार के साथ पुणे की एक झुग्गी में रहती थी। उसका पति उसे अक्सर पीटता भी था। लेकिन यह सब अतीत की बातें हैं। उसे आज भीड़ के बीच में उसके काले यूनिफॉर्म के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। उसकी सतर्क आंखें भीड़ पर निगाह रखती हैं। मैंने तो पुलिस की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन निजी कारणों से मैं पुलिस में नहीं जा सकी। मगर हमारी अकादमी में जो महिलाएं आती हैं, उन्हें भी पुलिस जैसी कठोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। उन्हें रोजाना कई किलोमीटर तक चलना या जॉगिंग करना अनिवार्य है। शुरू में जब कई महिलाएं यहां आती हैं, तो उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, लेकिन प्रशिक्षण के बाद उनका हौसला बढ़ जाता है। 'रणरागिनी' में कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों से लेकर विधवा और गृहणियां तक आकर प्रशिक्षण लेती हैं और अपने परिवार को आर्थिक मदद पहुंचा रही हैं।

**महज तीन वर्ष के भीतर हमारी अकादमी से 540 महिला बाउंसर जुड़ चुकी हैं।**

*- साक्षात्कारों पर आधारित*

## गंगा सफाई चुनावी मुद्दा क्यों नहीं

**गंगा विश्व की उन दस नदियों में से एक है, जिन पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। गंगा इस चुनाव में मुद्दा बने या न बने, लेकिन हमें यह समझना होगा कि केवल सरकारी परियोजनाओं के भरोसे ही गंगा को स्वच्छ नहीं बनाया जा सकता।**

**रोहित कौशिक**

पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में गंगा को जगह दी थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में अपने चुनाव प्रचार के दौरान गंगा की साफ-सफाई को लेकर बड़ी-बड़ी बातें की थीं, मगर गंगा को प्रदूषण से मुक्ति नहीं मिल सकी। अलबत्ता प्रयाग में कुंभ के दौरान गंगा में मिलने वाली गंदगी को रोकने में कुछ सफलता जरूर मिली थी। समय-समय पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी इस संबंध में कुछ प्रयास करता दिखाई देता है, लेकिन कटु सत्य यह है कि करोड़ों रुपये खर्च करने और अनेक परियोजनाएं बनाने के बावजूद गंगा को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी है। यह सही है कि गंगा के साथ भारतीय समाज की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि अंध आस्था अनेक नई समस्याओं को जन्म देती है। अगर गंगा के प्रति भारतीय समाज की आस्था सच्ची होती, तो न गंगा प्रदूषित हुई होती और न ही हमें गंगा की स्वच्छता के लिए सरकारी नीतियों के भरोसे रहना पड़ता।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के जवाब तलब करने पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकारों ने समुचित जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई हैं, जिसके कारण कानपुर से बक्सर और बक्सर से गंगा सागर तक की रूपरेखा तैयार करने में समस्याएं आ रही हैं। हरित अधिकरण ने उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड सरकार से कहा है कि वे प्रमुख स्थलों पर गंगा जल की गुणवत्ता की जानकारी हर महीने सार्वजनिक करें। हरित अधिकरण ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अगर तीस अप्रैल तक गंगा कार्ययोजना की रूपरेखा पेश नहीं की गई, तो वह सख्त कदम उठाएगा। केंद्र सरकार ने गंगा को साफ करने के लिए 'नमामि गंगे' परियोजना शुरू की थी, लेकिन इस योजना के अंतर्गत भी कम चुनौतियां नहीं हैं। गंगा के प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी अनेक बार दिशा-निर्देश जारी कर चुके हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक नतीजा ढाक के तीन पात ही है।

सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरमेंट (सीएसई) के विशेषज्ञों ने कुछ समय पहले कहा था कि गंगा की सफाई का अभियान इसी तरह चलता रहा तो आने वाले 30 वर्षों में भी गंगा साफ नहीं हो पाएगी। गौरतलब है कि गंगा के किनारे अनेक शहर, कस्बे और हजारों गांव स्थित हैं। प्रतिदिन इस आबादी का लगभग 1.3 अरब लीटर अपशिष्ट गंगा में गिरता है। गंगा के आस-पास स्थित सैकड़ों फैक्ट्रियां भी गंगा को प्रदूषित कर रही हैं। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या विस्फोट के कारण गंगा किनारे की आबादी तेजी से बढ़ी है। यह विडंबना ही है कि गंगा किनारे बसी इस आबादी ने भी गंगा को साफ-सुथरा रखने की कोई सुध नहीं ली, बल्कि इसे प्रदूषित ही किया। इस प्रदूषण के कारण ही आज हैजा, पीलिया, पेचिश और टाइफायड जैसी जल-जनित बीमारियां बढ़ती जा रही हैं।

एक ओर गंगा का प्रदूषण किसी न किसी रूप में बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर गंगा का उद्गम स्थल भी प्रदूषण की चपेट में है। वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान के ग्लेशियर अध्ययन केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार, गंगोत्री ग्लेशियर के माइक्रो क्लाइमेट में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इसकी सतह पर कार्बन और कचरे की काली पर्त जमा हो गई है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार, गंगा विश्व की उन दस नदियों में से एक है, जिन पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गंगा को सिर्फ चुनावी वैतरणी पार करने का जरिया बना दिया गया है? गंगा इस चुनाव में मुद्दा बने या न बने, लेकिन हमें यह समझना होगा कि केवल सरकारी परियोजनाओं के भरोसे ही गंगा को स्वच्छ नहीं बनाया जा सकता है।

**हरियाली और रास्ता**

## थोड़ी धार थोड़ा पसीना

***ऐसे श्रमिक की कहानी, जो मेहनत तो करता था, लेकिन अपने औजार पर नियमित धार नहीं।***

*मणि बहुत गरीब परिवार से था। वह हट्टा-कट्टा और मेहनती भी लग रहा था। लाला जी को लगा, शायद मणि उनके लिए लकड़ी काटने का काम अच्छी तरह से कर सकता है, लेकिन अभी नया लड़का है, तो कुछ दिन इसे परख लिया जाए। लाला जी ने मणि को काम पर रख लिया। मणि लगन से काम करने लगा। पहले दिन मणि ने 18 पेड़ काटे। लाला जी के यहां काम करने वाले सभी श्रमिक उसके काम से बहुत प्रभावित हुए। लाला जी भी उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों में उसके काम की गति धीरे-धीरे कम होने लगी। पहले सोलह, फिर पंद्रह, फिर बारह, और फिर दिन भर में उससे सिर्फ आठ ही पेड़ कट पाते थे। हालांकि वह काफी मेहनत करता था, पर न जाने क्यों अब उससे उतने पेड़ कट ही नहीं पा रहे थे। शीघ्र ही वह थक जाता था। अब उसे काम में भी बोरियत लगने लगी थी और उसे लगने लगा कि शायद वह इस काम के लिए बना ही नहीं। लाला जी के सारे श्रमिक भी अब उस पर ताना कसने लगे थे। अंत में एक दिन वह लाला जी के पास पहुंचा और नौकरी छोड़ने का प्रस्ताव रखा। लाला जी ने मणि की सारी बातें धैर्यपूर्वक सुनीं और कहा, 'बेटा, ऐसे हिम्मत हारने से काम कैसे चलेगा! क्या तुमने कभी अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने के बारे में भी सोचा है?' मणि यह सुनकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि यह तो कभी उसके मन में आया ही नहीं। लालाजी बोले, 'कई बार हम मेहनत करते-करते ऐसी बातों को नजरंदाज कर देते हैं। जो लोग, जो वस्तुएं हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती हैं, उन्हीं को हम रास्ते में खो देते हैं। मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हुए जरूरी है कि हम सफर का भी उतना ही आनंद लें, जितना कि मंजिल पर पहुंचने का होता है।*

**मेहनत के साथ अपनी कला और अपने औजारों को तराशना भी जरूरी है।**

**खुली खिड़की**

## किसके पास कितना सोना

**स्वर्ण भंडार विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों का पसंदीदा विकल्प है, जो राष्ट्रीय मुद्रा के मूल्य का समर्थन करता है। सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार अमेरिका के पास है।**

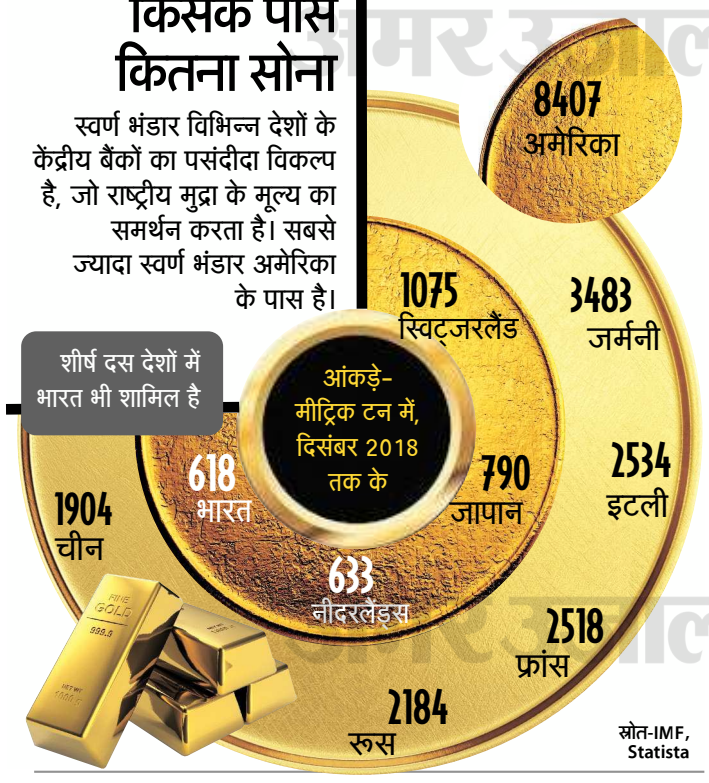


## विद्या से बड़ा धन नहीं

**चंद्रनगर** में एक विद्वान रहा करते थे। वह कहते थे, विद्या से बड़ा धन दूसरा नहीं। विद्यावान की सर्वत्र पूजा होती है। उनके तीन पुत्र थे, तीनों ने कड़ी मेहनत से शास्त्रों का अध्ययन किया। बड़ा पुत्र आयुर्वेद का प्रकांड विद्वान बन गया, जबकि दूसरा धर्मशास्त्रों का और तीसरा नीतिशास्त्र का विद्वान बना। तीनों ने एक-एक ग्रंथ की रचना की। प्रत्येक ग्रंथ में एक-एक लाख श्लोक थे।

चंद्रनगर के राजा विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन तीनों विद्वान अपने-अपने ग्रंथ लेकर पहुंचे। राजा ने उन्हें मोटे-मोटे ग्रंथ लिए देखा, तो बोले, इनमें लिखे सभी श्लोकों को पढ़ या सुन पाना तो मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मैं राजकाज के कामों में फंसा रहता हूं। इसलिए आप तीनों अपने-अपने ग्रंथों में से सार तत्व का एक-एक श्लोक सुना दें। आयुर्वेद के विद्वान ने कहा, आयुर्वेद में स्वस्थ रहने का एक सरल साधन है-जीर्ण भोजनमानेयः। यानी पहला भोजन पच जाने के बाद ही दूसरा भोजन करें। धर्मशास्त्र के विद्वान ने कहा, कपलः प्राणिनां दया। अर्थात ऋषि कहते हैं कि दया से बढ़कर और कोई धर्म नहीं। नीतिशास्त्र के विद्वान ने कहा, शुक्राचार्य कहते हैं-त्यजेद्दुर्जन संगतम। यानी दुर्जन की संगति कदापि न करें।

तीनों विद्वानों से शास्त्रों का सार सुनकर राजा गद्गद हो उठे और उन्होंने उन्हें पुरस्कार में एक-एक लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर ससम्मान विदा किया।

**सत्संग**

**-संकलित**